

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

सुप्रीम कोर्ट से राकांपा नेता नवाब मलिक को मिली राहत...

अंतरिम जमानत छह महीने और बढ़ाई गई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राफ़्तवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत गुरुवार को छह महीने के लिए बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू के इस पर आपत्ति नहीं जताने के बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत की अवधि बढ़ा दी। राजू ने कहा था कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।



अनुरोध किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा गुर्दे के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने गुण दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद गुण दोष के आधार पर जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

मलिक के खिलाफ ईडी का

पिछले साल 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई, 2023 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था

कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और पिछले साल 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ईडी ने भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। मलिक ने यह दावा करते हुए हाईकोर्ट से राहत का

नवी मुंबई में बने 400 से अधिक सार्वजनिक शौचालय...



मुंबई : शहर को खुले में शौच से मुक्त रखने की अपनी पहल में नवी मुंबई नगर निगम ने 406 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया है। हालांकि, इसे जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए, उन्होंने उन्हें Google मानचित्र पर चिह्नित किया है। इसके साथ, शहर में आने वाले आगंतुकों और यहां तक कि किसी काम के लिए बाहर रहने वाले निवासियों के पास एक अच्छा विकल्प है, और उन्हें खुले में पेशाब करने या प्रकृति की कॉल में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। NMMC ने पिछले कुछ वर्षों में अपने द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालयों में 6,857 सीटें उपलब्ध कराई हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

घर में मादक पदार्थों की प्रयोगशाला का भंडाफोड़!

1.06 करोड़ रुपये मूल्य का 'मेफेड्रोन' जब्त



मुंबई : उत्तरी मुंबई में मालवणी-कादिवली में एक घर में स्थापित मादक पदार्थ प्रयोगशाला से दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद कथित तौर पर 1.06 करोड़ रुपये मूल्य का 'मेफेड्रोन' जब्त किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मालवणी थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय अबरार इब्राहिम शेख और नूर आलम मेहबूब आलम चौधरी (24) के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा, 'शेख को पांच

जनवरी को एक ग्राम मेफेड्रोन और 100 बोतल थिनर के साथ पकड़ा गया था, जब पुलिस कादिवली पश्चिम इलाके में गश्त कर रही थी। उससे पूछताछ के बाद पुलिस को चौधरी के बारे में पता चला, जिससे उसने मादक पदार्थ खरीदा था।' उन्होंने कहा, 'जब हमने कादिवली पश्चिम में चारकोप इस्लाम कंपाउंड पर छापा मारा तो हमने चौधरी को मादक पदार्थ बनाते हुए पाया। हमने 1.06 करोड़ रुपये मूल्य की 503 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली 'मेफेड्रोन' बरामद की।' वरिष्ठ निरीक्षक चिमाजी अधव ने कहा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

महाराष्ट्र में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई 1.39 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित गुटखा किया जब्त...!

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने अंधेरी के डीएन नगर इलाके से 1.39 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित उत्पाद गुटखा जब्त किया है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां तीनों को शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महाराष्ट्र में गुटखा और सुगंधित तंबाकू की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है। ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। कुछ महीने पहले की बात करें तो महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस सप्ताह गुटखा और पान मसाला बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें एक लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया और एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज



की गई थी। एफडीए अधिकारियों ने जोगेश्वरी, मुलुंड, दादर, परेल, बोरीवली और नागपाड़ा में पान की दुकानों पर छापेमारी की। एफडीए (खाद्य) के संयुक्त आयुक्त शैलेश अधाओ ने कहा कि गुटखा, पान मसाला, मीठी सुपारी और सुगंधित तंबाकू - ये सभी चार वस्तुएं महाराष्ट्र में प्रतिबंधित हैं - लगभग 25 दुकानों

में खुले तौर पर पाई गईं, जिन पर छापा मारा गया था। गुटखा, एक चबाने योग्य तम्बाकू उत्पाद है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। इसका उपयोग मसूड़ों की बीमारी और दांतों की सड़न जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तंबाकू की मात्रा मुंह के कैंसर के खतरों को बढ़ाती है, जबकि निकोटीन लत में योगदान देता है।

नई दिल्ली : संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। सत्र की शुरूआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए आम चुनाव की घोषणा से पहले यह 17वीं लोकसभा का अंतिम संसद अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।



दें कि वर्ष 2019 में, लोकसभा चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में मतदान हुआ था। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में कई अहम बिलों पर चर्चा हुई। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में संध को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

धमार्णी-गोमा से अपेक्षा

हिमाचल मंत्रिमंडल में दो मंत्रियों की सवारी आ रही है तो गाजे-बाजे सहित तकनीकी शिक्षा, आयुष, युवा सेवाएं व खेल विभाग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जाहिर है राजेश धमार्णी व यादवेंद्र गोमा के हिस्से आए विभाग कहीं से छिटके तो कहीं पर अभी भी अटकें हैं। सुख सरकार की बनावट व सजावट में दो नए चेहरे, दो नई संभावनाएं, कुछ क्षेत्रीय वकालत और कुछ नया करने की एहसास लिए राजेश

धमार्णी को तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल व इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जिम्मा दिया है, तो यादवेंद्र गोमा को आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। इस तरह अभी भी कुछ महकमे किसी मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार नहीं दिखा सके। मंत्रिमंडल की नई परिभाषा में तीन मंत्रियों ने कहीं अपना दायित्व गंवाया है, लेकिन यह सरकार के एक साल के कामकाज की समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जनता के अनुभव में जहां अंगूर खट्टे हैं, वहां परिवर्तन की रिक्तियां हैं। हैं कई विभाग ऐसे भी जहां जनता के लिए सरकार की कार्यशैली में खोट है। यह कतरब्यौत है या सरकार के अगले कदमों की दुरुस्ती, लेकिन कई मंजिलों पे सन्नाटे अभी बरकरार हैं। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं का कौशल अगर मेडिकल कालेजों में हार रहा है, तो सरकार के प्रयत्नों में कहीं तो चुस्ती चाहिए। कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास की सतह पर पैदावार कम है, तो गारंटी के गोबर को उठाने की मशकत चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र को सर्दी में रुक गई विद्युत से सर्वप्रथम कुशल आपूर्ति चाहिए, तो गारंटी की मुफ्त बिजली के लिए कत्रव्यपरायणता का एहसास भी कराना होगा। कभी शहरी विकास मंत्रालय के स्तंभ रहे सुधीर शर्मा भले ही मंत्रिमंडल से बेदखल हो गए, लेकिन विभाग के स्वतंत्र प्रभार के लिए कोई तो नया चेहरा चाहिए। हो सकता है कि अलाहीन का चिराग मंत्रिमंडल के खालीपन को भरने के लिए एक अंतिम मंत्री को खोज रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शायद ही यह करिश्मा सरकार दिखाना चाहेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार बड़े ही तकनीक से नए मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहा है। एक तरह से दोनों ही नए मंत्रालय तुलनात्मक दृष्टि से युवा संबोधन पैदा कर रहे हैं।

युवा रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल व औद्योगिक प्रशिक्षण के हिसाब से आगे बढ़ा जाए, तो हिमाचल की आने वाली पीढ़ी की क्षमता में निखार आ सकता है। दूसरी ओर यादवेंद्र गोमा को मिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग भले ही बजट की दृष्टि से कमजोर महकमा दिखाई दे, लेकिन बच्चों को प्रेरणा के साथ उत्साहित व रोमांचित करने में महती योगदान कर सकता है। इसी तरह आयुष विभाग राज्य की सेहत के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से हैल्थ टूरिज्म को आवाज दे सकता है। कहना न होगा कि पूर्व में डा. राजीव बिंदल ने इस विभाग की उपयोगिता व दक्षता को चार चांद लगाते हुए पंचकर्म जैसी विधियों से अभिनव प्रयोग किए थे। अब अगर गोमा उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं तो हिमाचल अपनी हर्बल शक्ति से, केरल की तर्ज पर हैल्थ टूरिज्म का महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। इसी के साथ योग व अध्यात्म को जोड़कर पर्यटन पैकेज में बढ़ोतरी होगी। दरअसल हिमाचल में विभागीय समन्वय बढ़ाने के लिए मंत्रियों के ग्रुप बनाकर या मंत्रालयों के गठन को इस तरह करना चाहिए कि एक जैसे दायित्व समन्वित प्रयास से पूरे हो सकें। मसलन पर्यटन, सूचना एवं जनसंपर्क व कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग एक ही मंत्री के अधीन समाहित किए जाएं, तो पर्यटन विकास की दृष्टि में निखार आएगा। हिमाचल में अधोसंरचना निर्माण या निवेश मंत्रालय के तहत कार्य हो तो योजनाएं सशक्त होंगी। कृषि एवं बागबानी को जोड़कर एक ही मंत्री के तहत लाया जाए, तो ग्रामीण आर्थिकी के कई विषय अधूरे नहीं रहेंगे। इसी तरह कई विभागों को या तो छोटा मान लिया गया है या कर दिया गया है, जबकि हर विभाग का अपना स्कोप, सामर्थ्य, क्षमता व कार्य-संस्कृति निर्धारित है। मंत्रियों के कार्यभार आबंटन में क्षेत्रीय संभावनाओं व एहसास की पैमाइश भी होती है। बजट आबंटन की दृष्टि से महकमों को बड़ा माना गया, तो पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, वन, जलशक्ति, चिकित्सा व चिकित्सा की अहमियत बढ़ जाती है।

+91 99877 75650

editor@rokhoklekhani.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

बोरीवली के श्रीकृष्णानगर ब्रिज को वन विभाग से मिली अनुमति...

अगले चरण का काम जल्द होगा शुरू

मुंबई: बोरीवली में श्रीकृष्णानगर पुल के एक तरफ के निर्माण के लगभग नौ महीने बाद, वन विभाग ने अब दूसरी तरफ के काम की अनुमति दे दी है और दूसरे चरण का काम जल्द ही शुरू होने की संभावना है। चूंकि पुल बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में आता है, इसलिए वन विभाग से अनुमति के लिए काम रोक दिया गया था। यह अनुमति दिसंबर माह में मिली है। इसलिए शेष 11.30 मीटर चौड़ा पुल दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा।

मुंबई नगर निगम के ब्रिज विभाग द्वारा बोरीवली पूर्व के श्रीकृष्णानगर में दहिसर नदी पर ब्रिज का काम चल रहा है। इस पुल का काम चलने के कारण यहां के निवासियों को चार किमी का चक्कर लगाना पड़ रहा



था। इसलिए मार्च महीने में इस पुल का एक किनारा खोल दिया गया था। हालांकि, इस पुल का काम रुका हुआ था क्योंकि पुल के बाकी हिस्से के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता थी। यह अनुमति न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका। पिछले साल पुल के काम और उद्घाटन को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगरसेवक और बीजेपी के जनप्रतिनिधि के बीच विवाद हो गया था। इसलिए इस पुल का काम चर्चा में आया। पुल के आधे हिस्से का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ

शिंदे ने किया। लेकिन इस पुल के दूसरे हिस्से के लिए अनुमति की आवश्यकता थी। इसके चलते अन्य हिस्सों का काम रुक गया।

नगर निगम प्रशासन संजय गांधी पार्क के पास साइड के लिए वन विभाग से अनुमति लेने की कोशिश कर रहा था। तदनुसार, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगस्त 2023 में वन विभाग के तहत 0.0728 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी दे दी। यह अनुमति पत्र नागपुर और उद्घाटन को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगरसेवक और बीजेपी के जनप्रतिनिधि के बीच विवाद हो गया था। इसलिए इस पुल का काम चर्चा में आया। पुल के आधे हिस्से का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ

मुंबई में खुले में गंदगी फैलाने वालों पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई!



मुंबई: मुंबई में 'गहन सफाई' अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुंबई को साफ रखने के लिए गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस हिसाब से नगर पालिका ने अब तक 720 लोगों से 27 लाख से ज्यादा का जुमाना वसूला है। सबसे ज्यादा जुमाना दक्षिणी क्षेत्र से लगाया गया है। साथ ही टी वार्ड के मुलुंड इलाके में खुले में कचरा फेंकने वाले 27 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और दो लाख 70 हजार का जुमाना वसूला गया है।

हेडफोन जीवन को बेहतर बनाते हैं... एक्सप्रेस की टक्कर से युवक की मौत



रोहा: कान में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहे एक युवक को नेत्रावती एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। टक्कर में 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक

का नाम जयराम कृष्ण वाघमारे, करीब साढ़े 12 बजे जयराम कानों में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। इस बार पनवेल से रोहा की ओर आ रही नेत्रावती एक्सप्रेस ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद रेलवे पुलिस और रोहा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

ग्रांटरोड स्टेशन की इमारत में आग; कोई हताहत नहीं



मुंबई: पश्चिम रेलवे के ग्रांटरोड स्टेशन के पास स्लेटर रोड पर एक रेलवे भवन में सुबह करीब 11 बजे आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशकत से कुछ ही मिनट में आग बुझा दी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दक्षिण मुंबई में ग्रांटरोड रेलवे स्टेशन के पास सुबह व्यस्त समय के दौरान आग लगने की घटना हुई। आग टिकट खिड़की की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार के पास बिजली की खराबी के कारण लगी।

साई रिजॉर्ट में तोड़फोड़... अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक

मुंबई: उच्च न्यायालय ने सदानंद कदम के खेड़ स्थित साई रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी, जो कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब के करीबी माने जाते हैं। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दिया जो कदम और अन्य द्वारा शुरू की गई साई स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स नामक फर्म में भागीदार नहीं बन सका, और यह पहली नजर व्यस्त समय के दौरान आग लगने की घटना हुई। आग टिकट खिड़की की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार के पास बिजली की खराबी के कारण लगी।



योग्य है। भोसले ने कंपनी छोड़ दी और सहमति समझौते पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसलिए, भोसले के कंपनी छोड़ने के बाद, जमीन का स्वामित्व कदम के पास चला गया। नतीजतन, कदम पर एनए अनुमति के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली भोसले की निजी शिकायत में कोई दम नहीं है। इसके बाद भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जस्टिस जाधव ने प्रत्यक्षदर्शी टिप्पणी भी दर्ज की।

इस मामले में हमारे सामने जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे बेहद ठोस और गंभीर हैं। इसलिए, न्यायमूर्ति जाधव ने यह कहते हुए कदम के रिजॉर्ट के विध्वंस नोटिस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी कि किसी भी पक्ष को कानूनी प्रणाली का लाभ उठाने से रोकने के लिए मामले में अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक था। संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के रिजॉर्ट के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अपीलकर्ता प्राधिकारी को अगले आदेश तक कदम की अपील पर कोई सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

एसटी निगम 'सुरक्षा मिशन' लागू करेगा.. सुरक्षा अभियान दस दिनों तक जारी रहेगा



मुंबई: हर साल की तरह नए साल की शुरुआत में, एसटी कॉर्पोरेशन सुरक्षित यात्रा के बारे में एसटी कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 'सुरक्षा अभियान' चला रहा है। इस वर्ष यह अभियान 11 से 25 जनवरी तक एसटी के केन्द्रीय कार्यालय से लेकर समस्त आगर स्तर तक एक साथ चलाया जायेगा। सड़क परिवहन में सुरक्षित यात्रा का अत्यधिक महत्व है। पिछले 75 वर्षों में 'सुरक्षित यात्रा'

एसटी कॉर्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसलिए, एसटी ने आम यात्रियों के मन में विश्वसनीयता और सुरक्षित यात्रा की भावना पैदा की है। पूरे वर्ष दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता, विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एसटी चालकों को दुर्घटना रहित बस चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही 05 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक बिना दुर्घटना के एसटी बस चलाने वाले चालकों का विधिवत अभिनंदन किया जाता है। साथ ही 25 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी दुर्घटना के एसटी बसें चला रहे ड्राइवरों को 25 हजार रुपये का चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

ठाकरे को पता होना चाहिए कि एक स्पीकर किस उद्देश्य से मुख्यमंत्री से मिल सकता है : नार्वेकर

मुंबई : शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाने से पहले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने महाराष्ट्र में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, स्पीकर-मुख्यमंत्री की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद स्पीकर नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (9 जनवरी) को हलफनामा दाखिल किया है। उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर की मुलाकात पर आपत्ति जताई है। जिसको लेकर नार्वेकर ने कहा कि ठाकरे को पता होना चाहिए कि एक स्पीकर किस

उद्देश्य से मुख्यमंत्री से मिल सकता है। नार्वेकर ने कहा कि इस प्रकार के आरोप केवल दबाव डालने के लिए लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक स्पीकर मुख्यमंत्री से किन कारणों को लेकर मिलता है। एक विधायक होने के नाते भी कोई काम होते हैं, जिसको लेकर मेरी उनसे चर्चा होनी थी यह चर्चा 3 तारीख को होने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के चलते हम मिल नहीं पाए और

इसीलिए बाद में मुलाकात की।' उन्होंने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मेरे कई और भी कर्तव्य हैं, रही बात कोर्ट जाने की तो यह उनका संवैधानिक अधिकार है। फैसले के ऊपर सही समय पर बात की जाएगी। बता दें कि स्पीकर ने 7 जनवरी को दक्षिण मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'वर्षा' में शिंदे से मुलाकात की थी। अपने आवेदन में ठाकरे गुट ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत निर्णायक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष को 'निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप

से कार्य करना आवश्यक है।' इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष का आचरण विश्वास को प्रेरित करने वाला होना चाहिए और अपने उच्च पद पर जताए गए संवैधानिक विश्वास को उचित ठहराना चाहिए। आवेदन में कहा गया है, 'हालांकि, अध्यक्ष का वर्तमान कार्य निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।' आवेदन में कहा गया, 'स्पीकर का कृत्य कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह आवेदन उस चिंताजनक खबर के मद्देनजर दायर किया गया है कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय की समय सीमा से तीन दिन पहले 7 जनवरी को अपने आधिकारिक आवास पर शिंदे से मुलाकात की थी।

तेलंगाना-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मानव तस्करी, 24 फीसदी बढ़ी

मुंबई: मानव तस्करी भारत में भी एक बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, देश में हर दिन औसतन छह मामले दर्ज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तस्करी जबरन मजदूरी और यौन शोषण/वेश्यावृत्ति के लिए की जा रही। आंकड़ों के मुताबिक, तीन सालों (2020 से 2022) में इस कुकृत्य में 24 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2020 में जहां 1,714 मामले दर्ज हुए थे, तो 2022 में ये बढ़कर 2,250 हो गए। चिंता वाली बात यह है कि 16 फीसदी मामलों में पुलिस आरोपपत्र ही दाखिल नहीं कर पाती। करीब 80 फीसदी मामलों में आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र में तस्करी की सबसे ज्यादा शिकारयें दर्ज



होती हैं। इसके चलते भारत दुनिया में टीयर-2 श्रेणी में आता है। टीयर-2 श्रेणी उन देशों के लिए है, जहां सरकारें मानव तस्करी को रोकने के लिए न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक तरीके से काम लेना, यहां-वहां ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य मानव तस्करी की श्रेणी में आते हैं। मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक और पीड़ितों

की मदद करने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मानव तस्करी 40.5 फीसदी पुरुषों और 59.5 फीसदी महिलाओं को निशाना बनाते हैं। पिछले तीन साल में तस्करी के शिकार हुए 16,585 पीड़ितों में से 10,453 महिलाएं, वहीं 2021 में तो 62 फीसदी महिलाएं और 38 फीसदी पुरुष मानव तस्करी के शिकार हुए। मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 में जहां तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों में इसके 184-184 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2021 में तेलंगाना में इसके 347 और महाराष्ट्र में 320 मामले सामने आए।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक : नाना पटोले

मुंबई: एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और यह एक अलोकतांत्रिक फैसला है और यह पार्टी के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने स्वीकार किया कि असली शिवसेना 1999 थी, उन्होंने दोनों पक्षों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इस फैसले के बाद लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी को इस फैसले से दिक्कत होगी। मामले में



अंबादास दानवे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद में एलओपी और शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह फैसला गलत है। अगर उन्हें यह फैसला देना ही था तो उन्होंने इतना समय क्यों लिया? यह शुरू से ही टाइम पास

था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमता हुई है, तो क्या अनियमता हुई है, पहले वो बताएं? केवल आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना मुश्किल है। खासकर की तब जब निर्णय कानून के आधार पर लिया हुआ होता है। प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट जाने के बाद आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा दिया गया निर्णय अवैध है।

अजीत पवार खेमा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के ऐतिहासिक फैसले से खुश...

मुंबई: महाराष्ट्र में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला दे दिया। राजनीतिक रूप से मामला संवेदनशील था। इसलिए विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सुनाए गए फैसले का सीधा प्रसारण किया गया। इससे इस निर्णय के तार्किक आधारों को लोगों तक पहुंचाने में थोड़ी मदद भले ही मिली हो, लेकिन शिवसेना (उद्धव गुट) ने अस्वीकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा करने में देर नहीं की। शिवसेना के बाद ठंड भी विभाजन से गुजरी और उसका भी एक धड़ा अलग होकर मौजूदा सरकार का हिस्सा बना।



वहां भी शरद पवार की अगुआई वाला हिस्सा खुद को मूल पार्टी बताते हुए इन विधायकों की अयोग्यता का सवाल उठा रहा है। शिवसेना के बाद अब इसी महाने शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुए बगावत पर फैसला आ सकता है। बता दें कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत करते हुए भाजपा और

शिवसेना गठबंधन का दामन थाम लिया था। इसके बाद एनसीपी में भी विधायकों की अयोग्यता का केस चल रहा है। शिवसेना विवाद की तर्ज पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर भी फैसला करना है। स्पीकर के समक्ष मामले की सुनवाई जारी है। माना

जा रहा है कि 20 जनवरी तक क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कर लिया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर फाइनल सुनवाई 23 जनवरी को हो सकती है। इसके बाद 25 जनवरी को एक और सुनवाई के बाद 27 जनवरी को अंतिम सुनवाई कर ली जाएगी और 31 जनवरी को फैसला सुना दिया जाएगा। एनसीपी (अजीत पवार गुट) के प्रमुख सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी का मामला शिवसेना के मामले से अलग है। जहां मामला व्हिप की वैधता से संबंधित है और क्या प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा जारी किए गए व्हिप कानूनी रूप से वैध हैं।

मुंबई के लोगों को बारिश से राहत... धुला मुंबई का प्रदूषण

मुंबई: मंगलवार को हुई बारिश ने महानगर और आसपास के वायु प्रदूषण को धो डाला है। आमतौर पर इस सीजन में मुंबई की वायु गुणवत्ता 100 एक्वआई से अधिक रहती है, लेकिन बेमौसम बरसात से बुधवार को मुंबई की औसत वायु गुणवत्ता 85 एक्वआई दर्ज की गई। इससे पहले 27 नवंबर को महानगर की वायु गुणवत्ता 100 एक्वआई के नीचे यानी संतोषजनक स्तर पर पहुंची थी। ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर नागरिक, प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय बन जाता है। गत वर्ष भी अक्टूबर और



नवंबर में वायु गुणवत्ता का स्तर गिरने लगा था। बीएमसी के और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हस्तक्षेप और कार्रवाई के बाद प्रदूषण का बढ़ता स्तर कुछ हद तक काबू में आया, लेकिन मुंबई में जब-जब बेमौसम बरसात हुई, तब-तब अगले दो-तीन दिन तक हवा की क्वालिटी में ज्यादा सुधार हुआ है। मुंबई के मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं है।

ट्रक ड्राइवरों की फिर हड़ताल... मुंबई-अहमदाबाद रूट पर ट्रैफिक जाम

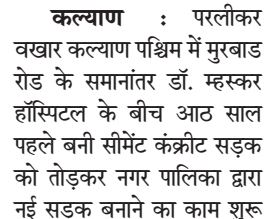


भयंदर: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागनाई पास के पास ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन के कारण पूरा राजमार्ग ट्रैफिक जाम के जाल में फंस गया है। इस विरोध प्रदर्शन में पहली बार रिक्शा चालक भी शामिल हुए। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवरों ने 'हित एंड रन' मामलों में सजा के कानूनी प्रावधानों में बदलाव का कड़ा विरोध किया है। इन प्रावधानों के खिलाफ ट्रक चालक पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर

रहे हैं। हालाँकि, समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। इस दौरान बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे ट्रक ड्राइवरों ने एक बार फिर मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सागनाई नायक में मुख्य सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर रिक्शा और ओला-उबर ड्राइवर भी शामिल हुए। इसके चलते वसई की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गये। लेकिन वाहनों को सड़क से हटाने में एक घंटे का समय बर्बाद हो गया।

कल्याण में कंक्रीट सड़क की तोड़फोड़... महस्कर अस्पताल से परलीकर सड़क पर रहेगी यातायात समस्या...

कल्याण : परलीकर वखार कल्याण पश्चिम में मुंबाड रोड के समानांतर डॉ. महस्कर हॉस्पिटल के बीच आठ साल पहले बनी सीमेंट कंक्रीट सड़क को तोड़कर नगर पालिका द्वारा नई सड़क बनाने का काम शुरू करने से क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई है। क्षेत्र के नागरिकों द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि यदि पहले गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाई गई होती तो क्या यह समय नगर पालिका के पास आता। परलीकर वखार से डॉ. महस्कर अस्पताल के बीच करीब 50 से 60 मीटर लंबी सड़क का निर्माण आठ साल पहले नगर पालिका ने ठेकेदार से कंक्रीट से करवाया था। ठेकेदार द्वारा घंटिया गुणवत्ता का काम करने और



क्योंकि यह देखा गया है कि ठेकेदार ने इसे खराब गुणवत्ता का बनाया है। यह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण विभाग ने इसे नए सिरे से बनाने की योजना बनाई है। इस कार्य के लिए सरकारी धन का उपयोग किया जाएगा। इस कंक्रीट सड़क को जेसीबी की मदद से बिछाया गया है। इस काम से सबसे ज्यादा परेशानी इस इलाके के स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बुढ़ों को हो रही है। क्षेत्र के नागरिक इस बात पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि यदि इस सड़क का कार्य गुणवत्ता के साथ किया गया होता तो नगर पालिका को इस सड़क के कार्य में राशि खर्च करने की नौबत नहीं आती।

नगर पालिका द्वारा सड़क का उचित रख-रखाव नहीं करने के कारण कंक्रीट की सड़क टूट गयी। गाड़ियों की भीड़ में कंक्रीट की सड़क के टुकड़े छूटने लगे। उस समय नागरिक आलोचना कर रहे थे कि नगर पालिका ने इस सड़क के लिए लाखों रुपये खर्च कर बर्बाद कर दिये। नगरपालिका ने पार्लिकर वखर और महस्कर अस्पताल के बीच सड़क के लिए ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है

मुंबई में राडार रोड, नवी मुंबई में 12 डंपर जल्ला!



नवी मुंबई: मुंबई के राडा रोडा नवी मुंबई इलाके में डंप कर रहे बारह डंपरों पर कार्रवाई की गई है। इस साल की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। इस संबंध में मंगलवार देर रात वाशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में राडा रोडा को गुप्त रूप से नवी मुंबई क्षेत्र में, विशेष रूप से वाशी खाड़ी और फोर्ट गावथन से लेकर उरण बेल्ट में लगाया जाता है। इसी तरह सिडको के सुरक्षा अधिकारी सुरेश मंगड़े को जानकारी मिली कि मुंबई से राडा रोडा लेकर कई डंपर नवी मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत भरारी टीम को शिव पनवेल हाईवे पर वाशी के लिए रवाना किया।

सड़कों की खराब हालत से पर्यटन पर असर



मुरुड : 350 साल पुराना जंजीरा और पञ्चदुर्ग किला, मुरुद, काशिद समुद्र तट, खोखरी गुंबद, नवाब काल का महल तालुक के विशेष आकर्षण हैं, जो साल भर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि मुख्य व आंतरिक सड़कों की खराब हालत के कारण कुछ महीनों से पर्यटकों की संख्या में कमी आयी है। यदि 30 किमी लंबी सालाव-मुरुद सड़क चार लेन बन जाती है, तो अलीबाग में रुकने वाले पर्यटक बिना किसी बाधा के सीधे मुरुद और दिवेगर, श्रीवर्धन तक पहुंच सकेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परिवहन सुविधाजनक हो जाएगा तो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसाय बढ़ेंगे और आजीविका की समस्या हल हो जाएगी।

जनता ने विधायक के रूप में महेंद्र दलवी को नेतृत्व सौंपा। नागरिकों को उम्मीद थी कि इन जन प्रतिनिधियों से तालुका में गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य और सड़कों का मजबूत जाल बना जाएगा, लेकिन पांच साल में मुरुड और शहर की तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है। मुरुड शहर को पर्यटन स्थल के रूप में 'बी' दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसकी तुलना में विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं। मुरुड तालुका में पर्यटन के अलावा कोई अन्य प्रमुख उद्योग नहीं है। बोरली से तालेखर बेल्ट तक के युवाओं के पास जेएसडब्ल्यू औद्योगिक समूह में आउटसोर्सिंग के अलावा कोई काम नहीं है। दिची बंदरगाह के माध्यम से कोंकण तट पर एक प्रमुख उद्योग का निर्माण किया गया है और अब बंदरगाह को प्रबंध निदेशक विजय कलंत्री से अदानी उद्योग समूह को स्थानांतरित कर दिया गया है। हालाँकि अमरदंडा क्षेत्र में छोटे और बड़े उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, कंपनी की ओर से कहा गया है कि अदानी समूह परियोजना के स्थानीय लोगों के विरोध का हवाला देते हुए अमरदंडा चरण को क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

पहले मनाया गर्लफ्रेंड का बर्थडे, उसी रात बैंक मैनेजर प्रेमिका का किया कत्ल

मुंबई: एक प्राइवेट बैंक में बतौर मैनेजर की काम करने वाली एक महिला की उसके प्रेमी ने कथित तौर हत्या कर दी। दोनों कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शोएब शेख (24), सितंबर 2023 से अमित कौर (35) को डेट कर रहा था। कौर तलाकशुदा थी और उसकी एक बेटी है। वह एक नवी मुंबई में बने 400 से अधिक सार्वजनिक शौचालय शहर को खुले में शौच से मुक्त रखने की अपनी पहल में नवी मुंबई



नगर निगम ने 406 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया है। हालाँकि, इसे जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए, उन्होंने उन्हें Google मानचित्र पर चिह्नित किया है। इसके साथ, शहर में आने वाले आगंतुकों और यहां तक कि किसी काम के लिए बाहर रहने

वाले निवासियों के पास एक अच्छा विकल्प है, और उन्हें खुले में पेशाब करने या प्रकृति की कॉल में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। NMMC ने पिछले कुछ वर्षों में अपने द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालयों में 6,857 सीटें उपलब्ध कराई हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सार्वजनिक शौचालयों में हाल ही में कोपर खैराने में पुनर्चक्रित कचरे का उपयोग करके निर्मित महत्वाकांक्षी शौचालय शामिल हैं, जो महाराष्ट्र में इस तरह की पहली पहल है। इससे अन्य शौचालयों का भी सौंदर्यीकरण हुआ है। इसके अलावा, नगर निकाय स्लम क्षेत्रों में निजी शौचालयों के निर्माण पर जोर दे रहा है। जिन मामलों में यह संभव नहीं है, वहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाता है। ठाणे बेलापुर राजमार्ग और सायन-पनवेल राजमार्ग सहित राजमार्गों पर विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध कराए गए हैं, जहां कई यात्री अपने गृहनगर के लिए बसें लेते हैं। जुई नगर में, जहां बड़ी संख्या में यात्री रहते हैं, पुरानी एनएमएमटी बसों को सौंदर्यीकरण के साथ आकर्षक शौचालयों में बदल दिया गया है।

विरार के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुआ हादसा... पानी की टंकी में गिरने से एक कर्मचारी की मौत

वसई: वसई के विरार नगर निगम के जल शोधन संयंत्र के टैंक में गिरने से एक नगर निगम कर्मचारी की मौत हो गई। मजदूर का नाम कैलास राउत (51) है और वह इस सेंटर में पंपमैन के तौर पर काम करता था। विरार पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। विरार पूर्व के फूलपाड़ा में मराठी स्कूल के पास नगर पालिका का जल शोधन संयंत्र है। इस केंद्र में बांध के पानी को शुद्ध कर वितरित किया जाता है। इस केंद्र में पंप का काम करने वाला कर्मचारी कैलास राउत रोजाना की तरह बुधवार की सुबह 7 बजे काम पर आया। वे टैंक का निरीक्षण करने के लिए ऊपर चढ़े थे। लेकिन काफी देर तक वे नीचे नहीं आये। सुबह करीब 9 बजे अन्य कर्मचारियों ने उसकी तलाश की। उस वक्त उसकी चप्पल टंकी के पास मिली थी। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। इसके बाद राउत का शव टैंक से निकाला गया। टैंक खुला है क्योंकि पानी से कचरा निकालना है। राउत नियमित पंप चालू करने का काम कर रहा था। लेकिन हम इस बात से हैरान हैं कि आज यह कैसे गिर गया, 'केंद्र में काम करने वाले दीवारमैन विशाल वैद्य ने कहा।



पर आया। वे टैंक का निरीक्षण करने के लिए ऊपर चढ़े थे। लेकिन काफी देर तक वे नीचे नहीं आये। सुबह करीब 9 बजे अन्य कर्मचारियों ने उसकी तलाश की। उस वक्त उसकी

चप्पल टंकी के पास मिली थी। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। इसके बाद राउत का शव टैंक से निकाला गया। टैंक खुला है क्योंकि पानी से कचरा निकालना है। राउत नियमित पंप चालू करने का काम कर रहा था। लेकिन हम इस बात से हैरान हैं कि आज यह कैसे गिर गया, 'केंद्र में काम करने वाले दीवारमैन विशाल वैद्य ने कहा।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com